डा० राम सुभग सिंह : जहां तक अहमदाबाद के महसाना का प्रश्न है वहां दो अक्तूबर से एक नई गाड़ी चलाई जाने वाली है। इस ओवर क्राउडिंग की दिक्कत को दूर करने के लिए। बम्बई से अमृतसर तक जो फंटियर मेल आती है उसको भी दो अक्तूबर से दिल्ली तक डीज़ल द्वारा चलाया जाएगा।

श्री उ० मु० त्रिवेदी : फंटियर मेल में आप टिकट नहीं देते हैं।

डा० राम सुभग सिंह : तीन तीन डिब्बे बढ़ा दिये जायेंगे चूंकि वह डीज़ल इंजन से चलेगी। हावड़ा से भी अमृतसर जो मेल ट्रन जाती है उसको भी डीज़ल द्वारा मुगलसराय से अमृतसर तक और उधर इलैक्ट्रिसिटी से मुगलसराय से हावड़ा की तरफ चलाया जाएगा। उस में भी तीन डिब्बे बढ़ जायेंगे।

श्री उ० मु० त्रिवेदी : पठानकोट एक्सप्रेस और देहरादून एक्सप्रेस का मैंने कहा है। फंटियर मेल में आप टिकट नहीं देते हैं। टिकट देने का भी इन्तज़ाम करोगे क्या ?

He has not answered the question. My question is this. Once you say that tickets are booked from Bombay to Delhi only and from Delhi to Bombay only in the Frontier Mail, will you allow third class passengers to enter in the middle stations?

डा० राम सुभग सिंह : उसको देख कर हो सका तो बढ़ा दिया जाएगा।

श्री ब्रज बिहारी महरोत्रा : थर्ड क्लास में ओवर क्राउडिंग होता है। उस में पंखे भी नहीं होते हैं और होते हैं तो अक्सर खराब रहते हैं। क्या सभी थर्ड क्लास के डिब्बों में आप पंखों की व्यवस्था करेंगे और साथ ही साथ यह भी देखेंगे कि वे चलते रहें ?

डा० राम सुभग सिंह: हर थर्ड क्लास की यह हालत नहीं है। कुछ हैं जिन में नहीं हैं। जिन कोचिज़ की बाकी उम्र पांच बरस से कम है उन में पंखों की व्यवस्था नहीं है। लेकिन और जो हैं उन में की जा रही है और अगले दिनों में कोई ऐसी कोच नहीं रहेगी थर्ड क्लास की जिसमें पंखा न हो।

Expansion of IISCO AND TISCO Plants

\+

***695. Shrimati Renuka Ray:**
Dr. Ranen Sen:

Will the Minister of **Iron and Steel** be pleased to state:

(a) whether any agreement has been reached with the World Bank in regard to the expansion of the IISCO and TISCO Steel Plants; and

(b) if so, the main features thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Iron and Steel (Shri P. C. Sehi): (a) IISCO have already executed a Loan Agreement with the World Bank on the 7th July, 1966, to meet the foreign exchange cost of their steel expansion programme from 1 million to 1.3 million tonnes of ingots per annum and also for importing spare parts and replacements.

So far as TISCO is concerned, although they have been permitted by the Government to negotiate a Loan with the World Bank to finance the foreign exchange cost of certain ancillary schemes to attain two million tonnes of ingot steel production per annum the loan is yet to be negotiated.

(b) A statemet is laid on the Table of the House in respect of the Loan negotiated by IISCO. [*Placed in Library. See* No. LT-6926/66].

Shrimati Renuka Ray: In the statement laid on the Table of the House there is no detail as to whether the type of steel that is to be made in the expansion scheme is going to be all needed for the productive capacity of India itself, or whether some of it is going to be exported abroad in an international market where there is slump in steel.

Shri P. C. Sethi: There is no need to detail these things as far as this

detail these things as far as this agreement is concerned because this is an agreement between the World Bank and the IISCO regarding the loan. As far as production pattern is concerned, both the things have been taken into consideration because now the export of steel is also taken into consideration.

Shrimati Renuka Ray: In a slump market? Does the introduction of modifications and new techniques mean an increase in the employment potential in India or does it mean that due to rationalisation or some other reason the employment potential is going to be reduced and retrenchment is to take place?

Shri P. C. Sethi: This is a very slight increase in production from one to 1.3, I have no exact figures whether it will particularly increase employment potenitial.

Shrimati Renuka Ray: Does the Government not go into these details about the private sector? They do things without knowing what the results would be.

The Minister of Iron and Steel (Shri T. N. Singh): There is o question of retrenchment of any persons.

Dr. Ranen Sen: Some years back it was decided by the Government of India that in the steel production there should be no more increase of capacity in the private sector and now we find gradually with the backing of the Government of India, the World Bank has given loans to IISCO and TISCO for expansion. It means that the private sector is expanding in the steel industry whereas according to the Industrial Policy Resolution it was Government of India's positioin not to increase the capacity of the private sector. May I know why this Government is trying to flout this Policy decision and increase the capacity of the private sector?

Shri T. N. Singh: May I point out that so far as the expansion of the existing plants in the private sector are concerned, this was covered by the Industrial Policy Resolution itself; that does not bar the expansion and that is why this marginal and other expansion had been allowed.

श्री भागवत झा आजाद : श्रीमती रेणुका राय के पूरक प्रश्न का स्पष्ट जवाब नहीं आया है इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि जब सरकार इतने बड़े कर्ज के लिए गारंटी दे रही है तो किस प्रकार के इस्पात का उत्पादन किया जाएगा, क्या उस इस्पात का उत्पादन किया जाएगा जिसकी देश को आवश्यकता है या उस इस्पात का उत्पादन किया जाएगा जोकि विदेशों को निर्यात किया जाता है ?

श्री प्र० चं० सेठी : मैंने कहा है कि जो लोन एग्रीमेंट है उस में प्रोडक्शन पैटर्न नहीं दिया गया है । लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि प्रोडक्शन पैटर्न के उनके साथ डिसाइड नहीं हुआ है । वह निश्चित हो चुका है । लेकिन इस समय मेरे पास पूरी जानकारी नहीं है कि उस में से कितना एक्सपोर्ट होगा और कितना यहां पर कन्ज्यूम होगा ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या यह सच नहीं है कि यह कम्पनी इतना बड़ा कर्ज लेकर जिस के लिए सरकार गारंटी रहेगी उस इस्पात का उत्पादन करेगी जोकि विदेशों को जाएगा और अपने देश की जो आवश्यकतायें हैं उन को पूरा नहीं करेगी ?

श्री त्रि० ना० सिंह : जितने स्टील प्लांट हैं प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों ने उन में जो प्रोडक्शन होता है उस में से कुछ अंश दोनों का ही एक्सपोर्ट भी हो रहा है और यहां की जो जहरियात हैं उनको भी वे मीटा कर रहे हैं । एक्सपोर्ट कर रहे हैं ।

श्री द्वा० दा० तिवारी : नेशनल और इंटरनेशनल दोनों जहरियात को पूरा करने के लिए स्टील की आजकल आवश्यकता है ।

हिन्दुस्तान की सरकार एक्सपेंशन भी कर रही है और न ही लोहे की मिलें चालू करने की भी कोशिश कर रही है । जिन चीजों का हिन्दुस्तान में ग्लट हो गया है, जिन की बिक्री नहीं होती है, जिन को सबसिडी दे कर बाहर भेजना पड़ता है, उन चीजों का उत्पादन न करके ऐसे लोहे के सामान का उत्पादन करना जिसकी देश को आवश्यकता है और जहां ही जो बिक सकता है और जिस को सबसिडी दे कर बाहर न भेजना पड़े और घाटा न उठाना पड़े, क्या इस पर आपने या प्लानिंग कमिशन ने विचार किया है और अगर किया है तो कसि निष्कर्ष पर आप पहुंचे हैं ?

श्री वि० ना० सिंह : मेरी समझ में गवनमेंट को या पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स को भी बराबर इस बात की तरफ ध्यान अवश्य देना चाहिए । उस में कितनी सबसिडी है मैं समझता हूं कि ज्यादा सबसिडी की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए और उम्मीद करता हूं कि ऐसी ही हालत आगे चलकर होगी । लेकिन साथ ही यह एकदम से कह देना कि किसी चीज का हमेशा ग्लट (अधिक उत्पादन) नहीं होगा, यह जरा मुश्किल है । आज तो दुनिया में, इंग्लैंड में और कई जगह स्टील का ग्लट है । यह खाली हिन्दुस्तान में नहीं है और जगह भी है ।

श्री रघुनाथ सिंह : इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि हम सेकेंड शिपयार्ड कोचीन में खोलने जा रहे हैं और हम को शिपयार्ड के वास्ते जितने स्टील की आवश्यकता होती है वह आज हम बाहर से स्टील प्लेट इम्पोर्ट करते हैं, तो क्या सरकार विचार करेगी कि हमारे जहाज को जिन स्टील प्लेटों की आवश्यकता है उस का उत्पादन भारतवष में हो सके ?

श्री वि० ना० सिंह : हमारे ख्याल में हमारे यहां प्लेट का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है और बढ़ भी रहा है । उस में और भी बातें होती हैं । कुछ स्पेशल क्वालिटी स्टील की बात आ जाती है उसके उत्पादन में कमी होती है, उस के फैब्रिकेशन आदि के कारखाने कम हैं, इन सब वजहों से कुछ इम्पोट करना ही पड़ता है ।

Mr. Deputy-Speaker: Shri Dinen Bhattacharya.

Shri S. M. Banerjee: Sir, I want to raise a point . . .

Mr. Deputy-Speaker: Order, order. The Minister has started answering the question.

Shri S. M. Banerjee: Before he answers, I want to make a point . . .

Mr. Deputy-Speaker Order, order.

12.00 hrs.

SHORT NOTICE QUESTION

Retrenchment of Workmen in Railway Electrification Project

+

SNQ. 18. Shri Dinen Bhattacharya:
Shri S. M. Banerjee:
Shri Tridib Kumar Chaudhuri:
Shri Umanath:
Shri Mohammed Koya:
Shri Biren Dutta:
Dr. U. Misra:
Shri Kolla Venkaiah:
Shri Madhu Limaye:
Shri H. N. Mukerjee:
Shrimati Renu Chakravartty:
Shri N. C. Chatterjee:
Shri Ram Sewak Yadav:
Shri Alvares:
Shri Nambiar:
Shri P. Kunhan:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether the Railway Board have ordered for large scale retrenchment of workmen in the Railway Electrification project;